ताल-बेताला



शशिकांत गुप्ते,
मोबाइल नं.
78984-88217

'अ' परिपक्वता या प्रगतिशीलता?

आज समाचार पत्र में एक खबर पढ़कर दुःख भी हुआ और कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी मस्तिष्क में उपस्थित हुए? वह आश्चर्य जनक खबर यह है कि मध्य प्रदेश के जिले के जिला मुख्यालय के जिला चिकित्सालय के दिव्यांग चिकित्सक कार चलाकर एक गर्भवती स्त्री के साथ अन्य सात लोगों को घायल कर दिया। दिव्यांग को सरल और बोलचाल की भाषा Disabled person और विगलांग को कहते हैं, Handicapped. दिव्यांगों के लिए चलाने के लिए दिव्यांग परिवर्तित वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। जिस चिकित्सक ने वाहन चलाया क्या वह वाहन दिव्यांग परिवर्तित वाहन था? क्या दिव्यांग चिकित्सक के पास लाइसेंस था? ऐसे व्यवहारिक प्रश्न स्थित होते हैं? मै इस मुद्दे पर गंभीरता से सोच रहा था। उसी समय मेरे व्यंग्यकार मित्र सीतारामजी का आगमन हुआ। आते ही सीतारामजी ने पूछा आज किस विषय पर लिख रहे हो? मैं ने मुद्दा बताया। मुद्दा सुनकर सीतारामजी हंसने लगे और मुझ से कहा कि दिव्यांग्य के द्वारा कार चलाने पर कुछ घायल हुए हैं आप इस मुद्दे पर इतना गंभीरता से क्यों सोच रहें हो? ऐसे साहसिक कार्य (adventure) तो अपने देश में आए दिन होते ही रहतें हैं। लगभग चार दशक पूर्व अहिल्य की नगरी में एक अबोध बालिका जिसने अपने जीवन के मात्र सात या आठ सावन ही देखें ते वह अबोध बालिका शहर के मध्य प्रमुख मार्ग पर कार चलाने वाली थी। बहुत से समाचार पत्रों में विज्ञापन भी प्रकाशित हुए थे और शहर में बैनर पोस्टर भी लगाए गए थे। लेकिन एक अखबार के एक खबरनवीस ने बहुत ही गंभीर,महत्वपूर्ण और न न्यायिक प्रश्न उपस्थित किया कि,क्या बालिका के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? यदि है तो नगर RTO ने अबोध बालिका को लाइसेंस कैसे दे दिया? यदि इस साहसिक कार्य के दौरान कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदार कौन? उक्त प्रश्नों के कारण उस साहसिक कार्य को प्रशासन द्वारा निरस्त कर दिया गया। मैने सीतारामजी से पूछा उक्त वाकये का मेरे मूल मुद्दे से क्या संबंध है? सीतारामजी ने कहा उक्त वाक़िया प्रशासन की गैरजिम्मेदारी को तो प्रकट करता ही साथ ही देश के पढ़े लिखे लोगों की समझ पर भी गम्भीर प्रश्न उपस्थित करता है। ऐसा साहसिक कार्य भी किस काम का जो स्वयं के साथ इतर बेकसूर लोगों के लिए भी घातक बने? सीतारामजी ने अपना वक्तव्य का जारी रखते हुए मुझ से कहा कि,आपने एक दिव्यांग के द्वारा कार चलाने को गम्भीर मुद्दा समझा है? आप सर्वांग संपन्न लोगों को देखों वे तो सर्वांग संपन्न होने के बाद भी बेतरतीब वाहन चलाते हैं। यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। मैने सीतारामजी से कहा इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो लोग सिर्फ यातयात नियमों की धज्जियां नहीं उड़ाते हैं,साथ कानून की अवहेलना करने में भी संकोच नहीं करते हैं। इसका मुख्य कारण इनके पास एक साथ दो लाइसेंस होते हैं,एक तो आरटीओ द्वारा प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा किसी जन प्रतिनिधि या किसी रसूखदार का पट्ठा होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण लाइसेंस होता है। पट्ठा मतलब किसी रसूखदार का अपना खास आदमी होता है। सीतारामजी ने मेरे वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा कि सच में इन दिनों रसूखदार के अलावा नव धनकुबेर जो समाज में संभ्रांत व्यक्ति कहलाते हैं। इनके लाडले मध्य रात्रि मादक पदार्थों का सेवन कर स्वयं लबरेज होकर वाहन भी स्वहृदय हाश्चद्रदस्र में चलाते हैं। इनके कीमती वाहन तो क्षतिग्रस्त होते ही हैं लेकिन निर्दोष राहगीर भी विकलांग होते है या भगवान को प्यारे हो जातें हैं। इन कथित संभ्रांत परिवारों में देश की आधी आबादी कहलाने वाली युवतियां मादक पदार्थों के साथ अहंकार के मद मदहोश होकर केवल बेतरतीब वाहन ही नहीं चलाती है बल्कि अपनी भारतीय संस्कृति को ताक में रखकर अपनी जुबां भी बहुत चलती है। साथ की 'अप 'शब्दों में माताश्री,पिताश्री,भाई बहन आदि रिश्तेदारों को भी याद कर लेती है। ऐसा कुछ रूढ़िवादी लोगों कहना है। ये रूढ़िवादी लोग क्या जाने प्रगतिशीलता क्या होती है? मेरे कथन का पुरजोर समर्थन करते हुए मुझे प्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी द्वारा रचित निम्न शेर सुनाया।

ये लोग पांव नहीं जेहन से अपाहिज हैं
उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है

मै भी शेर सुनने के बाद वाह वह और क्या बात है कहते हुए चर्चा को समाप्त किया।

कांग्रेस के सामने अपनों का वोट बचाने की चुनौती

भाजपा से लड़ने भोपाल आ रहा विपक्ष, 12 दिसंबर की वोट रक्षक रैली में राहुल-खरगे के साथ अखिलेश भी होंगे

भोपाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत अब तक यही रही है कि भाजपा के मुकाबले प्रदेश में वही एकमात्र मजबूत विपक्षी विकल्प है। लेकिन 12 दिसंबर को भोपाल में प्रस्तावित विपक्ष की वोट रक्षक रैली इसी राजनीतिक समीकरण को नई दिशा दे सकती है।

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के विरोध में होने वाली इस रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ समाजवादी पार्टी समेत इंडी गठबंधन के घटक दलों के नेता भी शामिल होंगे। कांग्रेस इसे लोकतंत्र और मताधिकार की रक्षा के लिए विपक्ष की एकजुटता बता रही है, लेकिन प्रदेश की राजनीति में इसके दूरगामी असर को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है।

राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए यह आयोजन महत्वपूर्ण है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सामने एक अलग चुनौती खड़ी हो सकती है। सवाल यह है कि जिस मंच से कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करेगी, क्या उसी मंच से उसके क्षेत्रीय सहयोगियों को प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर भी मिलेगा?

2023 का सीट बंटवारा विवाद फिर चर्चा में

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मध्य प्रदेश में सीटों को लेकर पहले भी टकराव हो चुका है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कम से कम छह सीटों की मांग की थी, लेकिन दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई।

इसके बाद अखिलेश यादव ने कांग्रेस नेतृत्व पर तीखे हमले किए और सपा ने अलग चुनाव लड़ा। उस घटनाक्रम ने स्पष्ट कर दिया था कि राष्ट्रीय स्तर पर साथ दिखाई देने वाले दल राज्यों में अपने राजनीतिक हितों को लेकर अलग रणनीति अपना सकते हैं। अब भोपाल की रैली में अखिलेश यादव की मौजूदगी को इसी पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। सियासी जानकारों का एक वर्ग मानता है कि सपा को प्रदेश में बड़ा मंच मिलने से भविष्य में वह अधिक सीटों पर दावा कर सकती है।



बसपा, आप और जीजीपी भी बदल सकते हैं समीकरण

कांग्रेस के सामने चुनौती केवल सपा तक सीमित नहीं है। बसपा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और आम आदमी पार्टी जैसे दल भी प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं। चंबल, विंध्य, बुंदेलखंड और आदिवासी बहुल इलाकों में इन दलों का सीमित लेकिन स्थानीय प्रभाव रहा है। करीबी चुनावी मुकाबलों में इन दलों की सक्रियता वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है। विशेष रूप से उन सीटों पर, जहां कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत-हार का अंतर कम रहता है। हालांकि यह भी सच है कि इन दलों का प्रभाव हर चुनाव और हर क्षेत्र में एक जैसा नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का एक वर्ग मानता है कि कांग्रेस को राष्ट्रीय गठबंधन की जरूरत और प्रदेश में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत के बीच संतुलन बनाना होगा।

बुंदेलखंड-विंध्य में सपा की पुरानी जमीन

मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का प्रभाव पूरे प्रदेश में भले ही सीमित हो, लेकिन उत्तर प्रदेश से सटे जिलों में उसका राजनीतिक आधार रहा है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा जैसे इलाकों में सपा की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर संगठन मौजूद रहा है। ऐसे में भोपाल की बड़ी रैली सपा के लिए प्रदेशव्यापी राजनीतिक पहचान बनाने का अवसर बन सकती है। अखिलेश यादव को राष्ट्रीय विपक्ष के प्रमुख चेहरे के रूप में मंच मिलने से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और नए समर्थकों तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकती है। इसका असर भविष्य में कांग्रेस के साथ सीटों के समझौते पर भी पड़ सकता है।

ओबीसी राजनीति में भी बढ़ सकती है हिस्सेदारी की होड़

मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी मतदाताओं की भूमिका निर्णायक रही है। कांग्रेस और भाजपा दोनों इस वर्ग में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती रही हैं। अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग, विशेषकर पीडीए की राजनीति के जरिए अपनी पहचान मजबूत कर चुके हैं। ऐसे में भोपाल के मंच पर उनकी मौजूदगी को केवल गठबंधन की औपचारिकता नहीं माना जा रहा।

कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी नेतृत्व और सामाजिक न्याय का संदेश देना चाहती है, लेकिन प्रदेश में सपा को मिलने वाली राजनीतिक दृश्यता भविष्य में उसके लिए प्रतिस्पर्धा भी पैदा कर सकती है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव राहुल गांधी के राजनीतिक फैसलों पर लगातार सवाल उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी के नेतृत्व और निर्णयों के कारण कांग्रेस की स्थिति कमजोर हुई है और पार्टी लगातार चुनावों में पिछड़ रही है। भाजपा इस रैली को भी कांग्रेस की राजनीतिक कमजोरी और नेतृत्व की असमंजस भरी रणनीति के रूप में पेश कर सकती है। दूसरी ओर कांग्रेस का तर्क है कि एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता जरूरी है।

प्रदेश को मिलेंगे दो एग्रीकल्चर क्लस्टर और दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

भोपाल। मध्यप्रदेश में कृषि और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर सहमति जताई है। प्रदेश में दो एग्रीकल्चर क्लस्टर और दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा 223 पुलों के निर्माण के लिए 643.14 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। करीब 600 करोड़ रुपये के सड़क संबंधी प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को प्रदेश के विकास से जुड़े प्रस्ताव लेकर आने के लिए बधाई दी। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश के लिए वैज्ञानिक कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा। इसे कृषि वैज्ञानिकों की टीम तैयार करेगी, ताकि प्रदेश की कृषि को आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों से जोड़ा जा सके। इसके साथ ही क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत प्रदेश में नर्सरी विकसित करने पर भी काम होगा। पीडीएमसी (प्रति बूंद अधिक फसल) योजना के तहत व्यापक सहायता देने पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सिंचाई के क्षेत्र में मध्यप्रदेश उल्लेखनीय काम कर रहा है। प्रदेश की सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े प्रस्तावों पर भी बैठक में चर्चा हुई और इनके समाधान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, बैठक में सड़कों, पुलों, मकानों, विभिन्न मिशनों और कृषि विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। 223 पुलों के निर्माण के लिए 643.14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जबकि लगभग 600 करोड़ रुपये के सड़क संबंधी प्रस्ताव भी सामने आए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, प्रहलाद जी और एदल सिंह जी सहित पूरी टीम प्रदेश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आई थी। बैठक उपयोगी और फलदायी रही।



एमपी में बदलने जा रहा मिड-डे मील का मेन्यू

भोपाल। एमपी के सरकारी स्कूलों में अब बच्चों की थाली में सिर्फ दाल-रोटी और सब्जी ही नहीं, बल्कि भुट्टे का कीस, दाल-बाफला, सेव-टमाटर की सब्जी, दाल-पानिया और बाजरे की राबड़ी जैसे लजीज पारंपरिक व्यंजन भी परोसे जाएंगे। बच्चों को रोज एक जैसा खाना खाने की मजबूरी से निजात दिलाने और उनके स्वाद को स्थानीय खानपान से जोड़ने के लिए सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना के मेन्यू में बदलाव किया है। अब सप्ताह में कम से कम एक दिन बच्चों को उनके अंचल का पारंपरिक और पौष्टिक भोजन देना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, बच्चों की थाली में हरी और गुलाबी चपाती भी नजर आएगी। पालक, मेथी, बथुआ और सहजन की पत्तियों से हरी चपाती, जबकि गाजर मिलाकर गुलाबी चपाती तैयार की जाएगी। राज्य शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मध्याह्न भोजन यानी पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना की नई मार्गदर्शिका जारी की है। इसमें भोजन की विविधता, पोषण स्तर, स्थानीय व्यंजनों, पकाने के तरीके और स्वच्छता से जुड़े कई बदलाव किए गए हैं। मेन्यू तैयार करने में अब सिर्फ अधिकारियों की भूमिका नहीं होगी, बल्कि स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी), अभिभावकों और विद्यार्थियों से भी उनकी पसंद के बारे में फीडबैक लिया जाएगा।

15 हजार भृत्यों की बदली पहचान, अब कहलाएंगे बाबू

दस साल से पदोन्नति का इंतजार कर रहे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिली राहत

भोपाल। सरकारी दफ्तरों में वर्षों तक फाइलें पहुंचाने, साहबों की सेवा करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में पहचान रखने वाले करीब 15 हजार कर्मचारियों के लिए अब परिचय बदल गया है। जो कर्मचारी अब तक भृत्य कहलाते थे, वे पदोन्नति के बाद लिपिक वर्ग यानी बाबू बन गए हैं। प्रदेश सरकार ने टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता प्रमाणपत्र (सीपीसीटी) की अनिवार्यता में शर्तों के साथ छूट देकर इन कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता खोल दिया है। इससे करीब 15 हजार कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी के पदों पर पहुंचने का मौका मिला है। इस फैसले का असर केवल कर्मचारियों के पदनाम और वेतनमान तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक पहचान से भी जुड़ा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि भृत्य पदनाम के कारण कई बार कर्मचारियों को सामाजिक स्तर पर असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अब पदोन्नति मिलने से उनके सम्मान और आत्मविश्वास में भी बदलाव आया है। प्रदेश में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या करीब 35 से 38 हजार बताई जाती है। इनमें लगभग 15 हजार कर्मचारी भृत्य के पद पर कार्यरत थे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाओं की चार श्रेणियां हैं-नियमित, आकस्मिक सेवा, अंशकालीन सेवा और स्थायी कर्मी। पदोन्नति की यह प्रक्रिया नियमित कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण रही। दरअसल, चतुर्थ श्रेणी से तृतीय श्रेणी में पदोन्नति के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर ज्ञान की योग्यता बाधा बन रही थी। भर्ती के समय इन कर्मचारियों के लिए ऐसी योग्यता अनिवार्य नहीं थी। लेकिन समय के साथ कार्यालयों में लिपिकीय कामकाज टाइपराइटर से कंप्यूटर पर पहुंच गया। ऐसे में पदोन्नति के लिए सीपीसीटी प्रमाणपत्र की शर्त पूरी नहीं कर पाने वाले कर्मचारी वर्षों तक इंतजार करते रहे।



3 दिसंबर को बैंकों में हड़ताल

भोपाल। मध्य प्रदेश में बैंककर्मी हड़ताल पर जा रहे हैं। 3 दिसंबर को 11 बड़े बैंकों के क्लर्क लेवल के करीब 8 हजार कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इससे बैंकों में लेन-देन पर असर पड़ेगा। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के खिलाफ बैंककर्मियों का यह प्रदर्शन है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाईज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लाईज फेडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर देशभर के लाखों बैंक कर्मचारी और अधिकारी 3 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल में शामिल होंगे। हड़ताली बैंककर्मियों की मांग है कि आईडीबीआई बैंक का निजीकरण और विदेशीकरण रोका जाए। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की रक्षा की जाए।

कॉलेजों की 85 हजार रिक्त सीटें भरने जनवरी में प्रवेश प्रक्रिया

भोपाल। मध्य प्रदेश के तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम कॉलेजों की खाली पड़ी करीब 85 हजार सीटों को भरने के लिए उच्च शिक्षा विभाग एक बार फिर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत जनवरी में विद्यार्थियों को कॉलेजों में प्रवेश का एक ओर मौका मिलेगा।

जुलाई में नियमित प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद प्रदेश के तकनीकी एवं प्रोफेशनल संस्थानों में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई हैं। इन सीटों को भरना कॉलेजों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।इसको देखते हुए तकनीकी शिक्षा संचालनालय (डीटीई) जनवरी में दोबारा प्रवेश प्रक्रिया आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विश्वविद्यालयों से सहमति ली जा रही है। सहमति मिलने के बाद संबद्ध कॉलेजों में कॉलेज लेवल काउंसलिंग (सीएलसी) के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। विभाग का उद्देश्य अधिक से अधिक खाली सीटों को भरकर कॉलेजों को राहत देना है. विद्यार्थियों को प्रवेश का अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है।



भोपाल में बनेगा वंदे भारत ट्रेनों का अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो

भोपाल। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए अत्याधुनिक मेंटेनेंस डिपो तैयार किया जा रहा है। भोपाल कोच फैक्ट्री परिसर में बन रहे इस डिपो के पहले चरण पर 146 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहां 6 नई अनुरक्षण लाइनें बनाई जा रही हैं। इनके तैयार होने के बाद वंदे भारत ट्रेनों का साप्ताहिक निरीक्षण करने के साथ मध्यम और लंबी अवधि का मेंटेनेंस भी भोपाल में हो सकेगा। फिलहाल रानी कमलापति स्टेशन स्थित डिपो में वंदे भारत ट्रेनों का केवल साप्ताहिक निरीक्षण किया जा रहा है। नए डिपो के बनने से भोपाल मंडल में संचालित इन ट्रेनों के रखरखाव की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही मेंटेनेंस के लिए दूसरे स्थानों पर निर्भरता भी कम होगी। रेलवे बोर्ड ने इस परियोजना को 7 अक्टूबर 2025 को मंजूरी दी थी। निर्माण कार्य 13 जून 2026 से शुरू हुआ है। रेलवे ने सितंबर 2027 तक डिपो तैयार करने का लक्ष्य रखा है। वंदे भारत ट्रेनों के अलावा एलएचबी कोच वाली ट्रेनों के रखरखाव की सुविधा भी विकसित की जाएगी। इसके लिए दो नई पिट लाइनों के निर्माण का प्रस्ताव है। इनके बनने से एलएचबी रेक का नियमित मेंटेनेंस कम समय में किया जा सकेगा। इससे भोपाल के मौजूदा अनुरक्षण केंद्रों पर काम का दबाव भी घटेगा।

शादी के खाने पर रहेगी फूड इंस्पेक्टरों की नजर

मैरिज गार्डन में होगी औचक जांच, कैटरिंग संचालकों के लाइसेंस, खाद्य सामग्री की एक्सपायरी डेट और साफ-सफाई की होगी पड़ताल

भोपाल।

शादी समारोहों में मेहमानों को परोसे जाने वाले खाने की गुणवत्ता अब खाद्य सुरक्षा विभाग की निगरानी में रहेगी। देवउठनी एकादशी के साथ शुरू हुए विवाह सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने भोपाल के मैरिज गार्डन, होटल के बैंक्वेट हॉल और कैटरिंग संचालकों के यहां औचक निरीक्षण की तैयारी की है। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा लाइसेंस से लेकर भोजन बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता, एक्सपायरी डेट और साफ-सफाई तक की पड़ताल की जाएगी। शहर में अगले दो से तीन महीने तक विवाह समारोहों की बड़ी संख्या में बुकिंग है। रोजाना हजारों मेहमान इन आयोजनों में भोजन करेंगे। ऐसे में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर विभाग ने निगरानी बढ़ाने का फैसला किया है। अलग-अलग क्षेत्रों में टीमें पहुंचकर जांच करेंगी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



बिना लाइसेंस कारोबार पर हो सकती है कार्रवाई

खाद्य सुरक्षा विभाग के दायरे में केवल मैरिज गार्डन ही नहीं, बल्कि होटल के बैंक्वेट हॉल और स्वतंत्र रूप से कैटरिंग का काम करने वाले संचालक भी रहेंगे। खाद्य कारोबार के लिए नियमानुसार लाइसेंस लेना और निर्धारित स्वच्छता मानकों का पालन करना अनिवार्य है। निरीक्षण में बिना लाइसेंस कारोबार संचालित मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पडऩे पर खाद्य कारोबार पर प्रतिबंध लगाने और प्रतिष्ठान का संचालन बंद कराने तक की कार्रवाई हो सकती है।

स्वामी मेसर्स एसोसिएटेड प्रिंटर्स एण्ड पब्लिशर्स (एम.पी.) प्रा.लि. इंदौर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मोनिका सेठ द्वारा 17, न्यू देवास रोड (संजय गांधी मार्ग) इंदौर से मुद्रित एवं 5, प्रेस कॉम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित संपादक-मोनिका सेठ, फोन नं. 3551753, 2434701, 2544433, समाचार पत्र से प्रकाशित समाचार के लिए सभी विवादों का न्याय क्षेत्र इंदौर रहेगा। समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के तहत जिम्मेदार*